

## **National Lok Adalat held on 14<sup>th</sup> May, 2022 for (Pre-Litigation & Pending matters)**

A National Lok Adalat for Pre-Litigation & Pending matters was organized today on **14<sup>th</sup> May, 2021** under the patronage of **Patron-in-Chief Hon'ble Mr. Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice**, High Court of Himachal Pradesh and under the able and innovative guidance of **Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge**, High Court of Himachal Pradesh and **Executive Chairperson, Himachal Pradesh State Legal Services Authority** in all the Courts in the State of Himachal Pradesh.

Hon'ble Executive Chairperson during video conferencing held with the Judicial Officers laid emphasis on effective identification and disposal of cases before National Lok Adalat. All the Judicial Officers were also impressed upon to identify old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters etc.

As per direction of Hon'ble Executive Chairperson, **a special drive was undertaken in the remote/tribal areas of districts of Chamba, Kinnaur and Lahaul & Spiti** for affording opportunity to the people of these areas for amicable settlement of disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the National Lok Adalat.

This time National Lok Adalat was not only organised but celebrated in the **spirit of an Utsav all over the state**. In this regard, a special drive was also undertaken for mass awareness about National Lok Adalat by associating local bodies, police, financial institutions, banks, NGOs, stakeholders, representatives of PRIs, PLVs, Asha/Anganwari workers, Public Transport Services etc. IEC material was distributed amongst general public containing contact numbers of all eleven DLSAs for the convenience of public, so that maximum number of cases are identified.

Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson, H.P. State Legal Services Authority inaugurated the first National Lok Adalat at Keylong and personally supervised proceedings taking place before the Lok Adalat Benches of National Lok Adalat at Sub-Divisional Legal Services Committee, Manali and at Keylong, district Headquarters of Lahaul & Spiti, where National Lok Adalat held for the first time and interacted with stakeholders/litigants. 240 cases were taken-up for settlement at Keylong, district

Headquarters of Lahaul & Spiti during the National Lok Adalat.

**The detail of Cases**

	<b>Pre-Litigation</b>	<b>Post-Litigation</b>	<b>Total</b>
Cases Taken-up	12447	31311	43758
Cases Settled	2240	17192	19432
Disposal Rate	17.99%	54.90%	44.40%



Inauguration of First National Lok Adalat at District Lahaul & Spiti, Headquarters Keylong by Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of HP & Executive Chairperson, HPSLSA



Interaction by Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of HP & Executive Chairperson, HPSLSA with Stakeholders and Litigants



## NATIONAL LOK ADALAT

# 19,205 cases disposed of in a day throughout state

**EXPRESS NEWS SERVICE**  
SHIMLA, MAY 14

IN THE National Lok Adalat organized in the state on Saturday, about 19,205 of 43,780 cases taken up for hearing in different courts were settled or disposed off, and approximately a sum of Rs 53 lakh was recovered/awarded to the claimants.

Member Secretary of Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Prem Pal Ranta, disclosed the information. He said that Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson of the state's legal services authority in-

augurated Keylong's first National Lok Adalat and personally supervised proceedings taking place before the Lok Adalat Benches of National Lok Adalat at Sub-Divisional Legal Services Committee, Manali and at Keylong. Around 240 cases were taken up for settlement at Keylong during the National Lok Adalat, he added.

He said that as per direction of Executive Chairperson, a special drive was undertaken in the remote/tribal areas of districts of Chamba, Kinnaur and Lahaul & Spiti to give people the opportunity to amicably settle disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the NLA.



## राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटान पर दिया गया जोर

शिमला, (आपका फ़ैसला)। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्री.लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 14 मई 2022 को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर

विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ, आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री.लिटिगेशन एवं पोस्ट.लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया। इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआईए पीएलवी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसी सामग्री जिसमें जन सुविधा के लिए सभी ग्यारह डीएलएसए के फोन नंबर भी अंकित किए गए थे को

आम जनता के बीच वितरित किया गया ताकि लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों की पहचान की जा सके। न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने केलांग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया और उपमंडल विधिक सेवा समिति, मनाली और लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग जहां पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों, प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 240 मामलों का निपटारे के लिए चिन्हित किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा किया गया।

## लंबित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

शिमला, 14 मई (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 14 मई को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों व आपराधिक कंपाऊंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार चम्बा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन एवं पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान

किया गया। इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पी.आर.आई., पी.एल.वी. आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया।

**केलांग में 240 मामलों को निपटारे के लिए किया गया चिन्हित :** हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष ने केलांग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इसमें लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया एवं हितधारकों व प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में 240 मामलों का निपटारे के लिए चिन्हित किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 4,780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा निपटान किया गया।



## प्रदेश में सजी लोक अदालतों में निपटाए 19205 मामले

स्टाफ रिपोर्टर - शिमला

प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। इसमें लाए गए 43780 मामलों में से 19205 मामलों का मौके पर निवारण किया गया और 530844573 रुपए की रिकवरी करके मौके पर ही भुगतान किया गया। इस लोक अदालत में प्रदेश के दुर्गम जिलों चंबा, किन्नौर व लाहुल-स्पीति में विशेष फोकस रहा और यहां प्राथमिकता से समस्याओं का निवारण किया गया। यह राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक उच्च न्यायालय की न्यायधीश एवं राज्य विधिक सेवा

● 53.08 करोड़ की लोक अदालत में हुई रिकवरी

प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी न्यायालयों में आयोजित हुई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमपाल रांटा ने बताया कि इस बार प्रदेश के दुर्गम जिलों खासकर लाहुल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ/आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया गया।

## राष्ट्रीय लोक अदालत में किया 19,205 मामलों का निपटारा

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्री लिटिगेशन के लंबित मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत प्रदेश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की देखरेख में आयोजित की गई। इसमें निपटारे के लिए विभिन्न देशों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से करीब 19205 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इस दौरान 53 करोड़ 8 लाख 44 हजार 573 रुपये की रिकवरी भी की गई। मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार चंबा, किन्नौर व लाहुल स्पीति जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन



### इन मामलों की हुई सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में पीठों के समक्ष पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक, बीमा, श्रम न्यायालय के मामले व आपराधिक कपाउडेबल मामलों का निपटारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल राटा ने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी।

मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए स्थानीय निकायों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पुलिस व गैर सरकारी संस्थानों का भी सहयोग लिया गया। न्यायाधीश सबीना ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने केलांग में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। यहां पर चिन्हित 240 मामलों का सफल पूर्वक निपटारा किया गया।





हैनिक भास्कर

शिमला, रविवार 15 मई, 2022 | 03

हिम

## राष्ट्रीय लोक अदालत में 43780 में से 19205 मामलों का किया गया निपटारा

भास्कर न्यूज़ | शिमला

प्री लिटिगेशन के लंबित मामलों के निपटारे के लिए शनिवार को प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई यह लोक अदालत प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश सबीना की देखरेख में आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न देशों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए जिनमें से लगभग 19205 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इस दौरान 53 करोड़ 8लाख 44 हजार 573 रुपए की रिकवरी भी की गई।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए स्थानीय निकायों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पुलिस, गैर सरकारी संस्थानों का भी सहयोग लिया गया।

## अमर उजाला

चंडीगढ़ | रविवार, 15 मई 2022

7

### लोक अदालतों में दिलाए

53.08 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में लोक अदालतें लगाई गईं। लोक अदालतों में 53.08 करोड़ रुपये दिलाए गए। लाहौल-स्पीति जिले के काजा में कुल 240 मामलों को चिह्नित किया गया है। इन लोक अदालतों में कुल 43,780 मामले लाए गए। इनमें 19,205 मामलों का निपटारा किया गया। अगली लोक अदालत 13 अगस्त को होगी। इस दौरान मोटर वाहन और चालान के मामलों को सुलझाया जाएगा। ब्यूरो

## पूरे प्रदेश में लगी अदालत

प्री-लिटिगेशन और लबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज 14 मई को माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य सरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया और लगभग 53,08,44,573/ की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को शाम 5 बजे तक वसूल/पुरस्कार दिया गया।



## राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया

केलांग। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में आज प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सवीना द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। न्यायमूर्ति श्रीमती सवीना के निर्देश के अनुसार जिला लाहौल -स्पीति में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति सवीना ने इस अवसर पर कुछ हितधारकों एवं पक्षकारों से बातचीत भी की तथा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता एवं मामलों के निपटारे सम्बन्धी जानकारी भी दी। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा कहा कि लोक अदालत में लगभग 240 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते से किया।



हिमाचल दस्तक  
www.himachaldastak.com

दिलला, एदिवार 15 नई, 2022

# हिमाचल

## विभिन्न पीठों के समक्ष जाए जाए 43780 मामले, लजाभा 53 करोड़ की राशि वसूली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा 19205 मामले

विशेष संवाददाता ■ दिल्ली

शनिवार को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न पीठों के समक्ष 43780 मामले जाए गए, जिनमें से लगभग 19205 मामलों का निपटारा किया गया है। लगभग 53 करोड़ 8 लाख 44 हजार 573 रुपये की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों से वसूल की गई है।

अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को आयोजित की जाएगी। न्यायाधीश सबीना जोकि स्टेट लीगल सर्विसेज की कार्यकारी अध्यक्ष हैं के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान तथा नेगोशी, बल इन्स्ट्रुमेंट्स मामलों

के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।

आज की लोक अदालत प्री-लिटिगेशन और लिखित मामलों के निपटारे के लिए थी। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के

### अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को आयोजित होगी

समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कपड़ों के लिए भी प्रेरित किया गया।

### उत्सव की भावना से मनाया गया कार्यक्रम

इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, विधायक संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, रिटायरमेंट, पीआरआई, पीएनबी, अशा/आनलडी कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसीएनबी जिसने जन सुनिवेश के लिए एक विशेष अभियान के फोन नंबर भी अंकित किए गए थे, को आज जता के बीच वितरित किया गया लॉक लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक जानलों की पहचान की जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लॉक-स्पीड के तिलानुष्ठान के ताला नै 240 जानलों का निपटारे के लिए दिहल किया गया।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के लिटिगेशन एवं मोटर-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन एवं मोटर-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान का अवसर प्रदान किया गया।



# राष्ट्रीय लोक अदालत में 19205 गांवों का निपटारा

दावेदारों को मिली 53 कपेड लोक अदालतों में सुनवाई केलवा में लोक अदालत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 लाख से अधिक की रकम को आए थे 43780 गांवों 240 गांवों का हुआ निपटारा किया लोक अदालत का आयोजन

शिमला, 14 मई (ब्यूरो) : प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस मोहम्मद रफीक व उच्च न्यायालय की कार्यकारी अध्यक्ष प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के मार्ग दर्शन में शनिवार को प्रदेश के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के समक्ष निपटारे के लिए 43780 मामलों में से 19205 का निपटारा किया गया। इस दौरान दावेदारों को 53 करोड़ 8 लाख 44 हजार 573 रुपए की राशि प्रदान की गई। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में आयोजित लोक अदालत में 240 मामलों का निपटारा किया गया। जिला

एवं सत्र न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सबीना ने राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रथमी पहचान और निपटारन पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक, बीमा, श्रम न्यायालय, आपराधिक कंथाउडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में लोक अदालत के दौरान हितधारकों के साथ संवाद करती राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सबीना। एक विशेष अभियान चलाया गया और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रिय लोक अदालत के माध्यम से प्री एवं पोस्ट-लिटिगेशन मामलों के सीाददपूर्ण



निपटारन का अवसर प्रदान किया गया। भावना से मनया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि समूचे राज्य में स्थानीय निकायों, पुलिस, वितीय न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का सस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, आयोजन किया गया, बल्कि उत्सव की हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सांविजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सबीना ने केलंग में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। उन्होंने उपमंडल विधिक सेवा समिति मनाली और लाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में होने वाली लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों, प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को प्रदेश में अगली लोक अदालत का आयोजन होगा।



## 19K cases settled at Lok Adalat

SHIMLA, MAY 15

A total of 43,780 cases were taken up at the National Lok Adalat before different benches in the state. As many as 19,205 cases were settled/disposed of yesterday.

Approximately Rs 53 crore were recovered/awarded to the claimants. Justice Sabina inaugurated the first National Lok Adalat at Keylong in Lahaul and Spiti. — TNS

# लोक अदालत में मौके पर निपटारा 825 मामलों

## किशोर जिला के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकॉमिण्डो में हुआ आयोजन

किशोर जिला के न्यायिक न्यायालय परिसर रिकॉमिण्डो में शरिष्ठ दीवानी एवं एवं न्यायिक दंडाधिकारी श्रीलक्ष्मी कुमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई।

लोक अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई. अर्थात् निधम से संबंधित मामलों, मनी-रिकवरी, भ्रम विवाद, रिजल्टी व घानी, भरण-पुष्पण व अन्य (आर्थोपिक, कम्पाउंडिंग व दीवानी

विवाद) से संबंधित मामलों प्रस्तुत किए गए।

इसके आर्थिक न्यायालयों में लॉक मासले किनमें क्रिमिनल कम्पाउंडिंग अर्केन, धारा 138 के तहत एन.आई. अर्थात् निधम से संबंधित मामलों, मनी-रिकवरी, काहन दुपेटा, भ्रम विवाद, विधुत व घानी की वल, वैवाहिक विवाद (तलाक की छी फुलर), यू-ओ थिएटल, सेकरो से संबंधित तनखो व भते, सेवो नवति से संबंधित मामलों, राजस्व मामले (केवल डिजा व डबल न्यायालय में लॉक) व अन्य दीवानी मामलों (किराया, मुख भोग अधिकार (गुजरा भला), रिजल्ट संबंधी, मिश्र प्रदर्शन सट) संबंधित लगभग 707 मामलों शरिष्ठा से तथा लोक अदालत में 315 मामलों का निपटारा किया गया।

श्रीलक्ष्मी कुमर ने कहा कि किशोर जिला में अब एक लोक अदालतों में से सबसे ज्यादा मामलों इस बार के लोक अदालत में सपने आए हैं, यहाँ 35 वर्षों से चले आ रहे मुगो देवो न्यायक बुजुर्गों महिला का एक मामलों को भी इस लोक अदालत में निपटारा गया तथा जब तक सभी केसों का निपटारा नहीं किया गया तब तक सी.डी.एम. द्वारा लोक अदालत का समापन नहीं किया गया।

सोमवार जिला विधिपक, सेवार्थ शरिष्करण किशोर निजारात घानी में जारी प्रेस बयान में बताया कि 6 घंटों में राष्ट्रीय लोक अदालत में उद्वेग-गुण-मामलों की कुल संख्या 1614 थी तथा मौके पर 825 मामलों को निपटारा गया तथा इस दौरान निपटारा शरिष्ठा 4 करोड़ 87 लाख 61 हजार 745 रुपए थी।



रिकॉमिण्डो : न्यायिक न्यायालय परिसर में लोक अदालत में शरिष्ठ दीवानी कुमर एवं न्यायिक दंडाधिकारी मामलों को निपटारे हुए।

# National Lok Adalats in Himachal Settle 19205 Cases, Award Rs 53.04 Crore as Compensation Claimants

Category: [Breaking News](#) Published: 14 May 2022 Hits: 77

**Author: Kuldeep Chauhan, Editor, HimbuMail**



SHIMLA: A record number of cases were taken up in the **National Lok Adalat** held on May 14 before different benches for settlement across the state. Out of these, as many as 19205 cases were settled or disposed off and the judges awarded over ₹53.08 Crore compensation to the claimants.

It was for the first time that **Ms. Justice Sabina, judge High Court of Himachal Pradesh, who is also Executive Director, HP State Legal Services Authorities (HPSLA)**, inaugurated the National Lok Adalat at Keylong in the

**Inauguration of First National Lok Adalat at District Lahaul & Spiti at headquarter Keylong**

landlocked tribal Lahaul-Spiti district. As many as 240 cases were taken up for settlement there giving justice to the tribals at door-step on Saturday.

## National Lok Adalat Gives Relief and Creates Goodwill among Litigants

Considering the response of the litigant public, National Lok Adalat today turned out to be an Utsav creating good-will among litigants as they come out in large number for settlement and got much-needed relief in pending cases.

National Lok Adalat was organized under patronage of Patron-in-Chief Hon'ble Mr. Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice, Court of Himachal Pradesh and under innovative guidance of Ms. Justice Sabina, in all the Courts in the state on May 14.

The massive response to the National Lok Adalat was possible as HPSAL left no stone unturned to reach out to the litigants and stakeholders through new and various modes of social and web media including traditional means of communication.

## Massive Awareness Campaign

Executive Chairperson, HPSLA held video-conferencing with judicial officers, laid emphasis on effective identification and disposal of cases before National Lok Adalat.

**Executive Chairperson** impressed upon the judges to identify old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters, said Prem Pal Ranta, member-secretary, HPSLA, legal authority which facilitates organization of National Lok Adalat in the state.



As per direction of Executive Chairperson, HPSLA launched a special drive in the remote, tribal areas of districts of Chamba, Kinnaur and Lahaul-Spiti.

People in these areas got an opportunity for amicable settlement of disputes both at pre-litigation and post-litigation stage in the National Lok Adalat, Ranta said.



HPSLA also roped in local bodies, police, financial institutions, banks, NGOs, stakeholders, representatives of PRIs, PLVs, Asha/Anganwari workers, Public Transport Services to create awareness about National Lok Adalat that paid its dividends.

Not only this, publicity material including pamphlets were distributed amongst general public containing contact numbers eleven District Legal Service Authorities(DLSA). This made easy for locals to contact the DLSA that led to a good response National Lok Adalat.

## **Next National Lok Adalat on August 13, 2022**

Next National Lok Adalat will be held on 13<sup>th</sup> August, 2022. As per directions of Executive Chairperson in coming times **Sj Lok Adalats will be held for Motor Vehicle Challans and Negotiable Instruments Act Cases in areas where pendei** more.

# People of Lahaul-Spiti Get Justice at Door-step in First National Lok Adalat at Keylong

Category: [Breaking News](#) Published: 14 May 2022 Hits: 205

**Author: Kuldeep Chauhan, Editor, HimbuMail**

- [Lok Adalat](#)
- [Past Lok Adalat in Himachal](#)
- [High Court on vacant posts](#)



**Inauguration of First National Lok Adalat at District Lahaul & Spiti at headquarter Keylong**

SHIMLA/KEYLONG: Propelled by a desire to deliver justice at the door step to the tribals across the 13050 ft high Rohtang Pass, Ms. Justice Sabina, judge of the High Court of Himachal Pradesh inaugurated the first National Lok Adalat at Keylong in the district of Lahaul-Spiti on Saturday.

Residents of landlocked Lahaul-Spiti district are getting an "instant justice" at their door step as many as 240 cases which were pending for the settlement at the National Lok Adalat on May 14.

Ms. Justice Sabina, who is also **Executive Chairperson, HP State Legal Services Authority (HPSLSA)** personally supervised proceedings taking place before the Benches of National Lok Adalat at Keylong and Manali.

National Lok Adalats are being held under patronage of Chief Justice of High Court Mohammad Rafiq and supervised by executive chairperson Ms Justice Sabina across the state on May 14.

Ms Justice Sabina was assisted by Prem Pal Ranta, member-secretary, HPSLSA, which created history by holding the first National Lok Adalat at Keylong in the landlocked Lahaul-Spiti.

Ms. **Justice Sabina** also interacted with local stakeholders and litigants.



**Interaction by Hon'ble Mrs. Justice Sabina, Executive Chairperson with Stakeholders and Litigants**

Instant justice delivered through the National Lok Adalat is all the more relishable and special for people of Lahaul-Spiti as there is no judicial court for over 35000 people, who live in the landlocked Tribal valley since time immemorial.

## **The main reason for this is that there is little crime taking place in tribal belt.**

The Atal Rohtang Tunnel came in handy for holding of the National Lok Adalat there. It has cut traveling time bypassing Rohtang Pass and It takes just an hour to reach Keylong from Manali, said the residents.

"It is a historic moment for the people of snowbound Lahaul-Spiti across the Mighty Rohtang Pass", said Prem Lal Yuterpa, a resident of Sashin. "There is little crime here. But people get instant relief in cases related the excise and other disputes at their door steps", said Tashi Harpa, former President of Lahaul-Spiti hoteliers association.

They also got justice at their convenience and without spending much and traveling to Kullu or Shimla for over 350 said Prem Katoch, ex-President of Save Lahauli-Spiti Society, an NGO working to protect interests of people of district.

**Legal justice system is an otherwise expensive and time-consuming, added Katoch. Such Lok Adalat should be organised from time when cases pile up, he added.**



Ranta said National Lok Adalat was also held at Sub-Divisional Legal Services Committee, Manali, besides at Keylong, district Headquarters of Lahaul & Spiti. It was a great success as litigants get instant justice without delay and cost, he added.





राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला लाहौल-स्पीति के मुख्यालय केलांग में लोक अदालत के शुभारंभ पर प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सवीना चर्चा करते हुए। -संवाद

## आपसी सुलह से निपटाए 240 मामले

संवाद न्यूज एजेंसी

**केलांग (लाहौल-स्पीति)।** जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में शनिवार को पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सवीना ने घाटी के हितधारकों एवं पक्षकारों से बातचीत की और प्राधिकरण की ओर से

### केलांग में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

विधिक सहायता एवं मामलों के निपटारे संबंधी जानकारी दी।

प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा कहा कि लोक अदालत में लगभग 240 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते से किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना केस, बीमा संबंधी मामले, वैवाहिक

मतभेद, दीवानी मामले, आपराधिक कंपाउंडिंग मामलों के साथ-साथ अन्य श्रेणी के मामलों को निपटाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अमरदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक लाहौल-स्पीति मानव वर्मा, सहायक आयुक्त रोहित शर्मा, अधिवक्ता विशन सिंह और संदीप नलवा भी उपस्थित रहे।